नईदुनिया

बांग्लादेश के रमना बटामुल नरसंहार केस में दोषियों की सजा पर फैसला आठ मई को

ढाका

बांग्लादेश में दिल दहला देने वाले 2001 के रमना बटामुल नरसंहार केस में हाई कोर्ट आठ मई को फैसला सुनाएगा। जस्टिस मुस्तफा जमान इस्लाम और जस्टिस नसरीन अख्तर की पीठ ने आज फैसला सुनाने की तारीख आठ मई तय की। पीठ ने 18 फरवरी को मृत्युदंड संदर्भों (मृत्युदंड की पुष्टि के लिए ट्रायल कोर्ट के दस्तावेज) और मामले में दोषी ठहराए गए आरोपितों की अपीलों पर सुनवाई पूरी कर सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

खबर में अभियोजन के हवाले से यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि 14 अप्रैल, 2001 को राजधानी के रमना बटामुल में छायानौत के 1408 पहला बैशाख समारोह के दौरान दो बम विस्फोट हुए। देश को दहला देने वाले इन बम धमाकों में 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुई थे। 23 जून, 2014 को ढाका की एक अदालत ने मुफ्ती अब्दुल हन्नान, मौलाना अकबर हुसैन उर्फ हेलालुद्दीन, मौलाना मोहम्मद ताजुद्दीन, हाफेज जहांगीर आलम बदर, मौलाना अबू बकर उर्फ सेलिम हवलदार, मुफ्ती शफीकुर रहमान, मुफ्ती अब्दुल हई और आरिफ हसन सुमन को मौत की सजा सुनाई। इसके अलावा मौलाना अबू ताहेर, मौलाना सब्बीर उर्फ अब्दुल हन्नान, मौलाना याहिया, मौलाना शौकत उस्मान, मौलाना अब्दुर रउफ और शहादत उल्लाह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सभी दोषी इस्लामी समूह हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी के सदस्य हैं।

हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी बांग्लादेश के सभी आतंकी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने में शामिल देश के सबसे कुख्यात आतंकवादियों में से एक मुफ्ती अब्दुल हन्नान को 13 अप्रैल, 2017 को काशिमपुर उच्च सुरक्षा जेल में फांसी दी जा चुकी है। हन्नान को 21 मई, 2004 को सिलहट में तत्कालीन ब्रिटिश उच्चायुक्त अनवर चौधरी पर ग्रेनेड हमला करने के लिए फांसी दी गई थी। उस मामले में कुछ अन्य आरोपित अभी फरार हैं।

न्यूज ब्रीफ

भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले तीन दिनों के नेपाल भ्रमण पर काठमांडू पहुंचे

काठमांडू। भारत की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले

नेपाल के साथ संबंध मजबूत करने और प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ जुड़ने के उद्देश्य से तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर बुधवार को काठमांडू पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान चौथाईवाले प्रधानमंत्री और मुख्य विपक्षी दल के नेता पुष्पकमल दहाल प्रचंड, सत्तारूढ़ गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं, राजनीतिक मोर्चों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। काठमांडू आगमन पर चौथाईवाले ने बताया कि इस यात्रा के दौरान उनकी चर्चा राजनीतिक सहयोग, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर केन्द्रित रहने वाली है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत की संभावित यात्रा के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। ओली के प्रधानमंत्री बनने के दस महीने के बाद भी उनकी भारत यात्रा नहीं हो पाई है। उनकी यात्रा नेपाल के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ संबंधों को गहरा करने और ऐसे समय में सद्भावना को बढ़ावा देने की व्यापक पहल का हिस्सा है, जब दोनों पड़ोसियों के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान सीमित हो गया है। चौथाईवाले के नेपाल भ्रमण को नेपाली राजनीतिक दल के साथ भाजपा की निकटता को और अधिक प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

पाकिस्तान को जासूसों ने किया आगाह, भारत कभी भी कर सकता है सैन्य कार्रवाई, 24 से 36 घंटे बेहद अहम

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की हुकूमत को उसके जासूसों ने आगाह किया है। जासूसों ने कहा है कि यह चौकन्ना रहने का वक्त है। भारत कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। आने वाले 24 से 36 घंटे बेहद अहम हैं। जासूसों की यह चेतावनी भारत के जम्मू-कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद आई है। सूचनामंत्री अताउल्लाह तरार ने माना है कि संघीय सरकार को ऐसी खुफिया रिपोर्ट मिली है। इस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। सूचनामंत्री तरार ने कहा कि विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि भारत दोनों देशों के बीच तनाव के बीच अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इस हमले के लिए नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को दोषी ठहराया है। तरार ने कहा कि हालांकि इसके लिए भारत ने कोई सबूत नहीं दिया है। इस बीच भारत के अपनी सेना को खुली छूट देने से समूचे मुल्क में हड़कंप मचा हुआ है। भारत की इस अहम घोषणा से पसीना-पसीना तरार ने कुछ घंटों बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम घटना का बदला लेने के लिए 24-36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है। अगर मुल्क पर हमला होता है तो उसके परिणाम विनाशकारी होंगे। पाकिस्तान की फौज जवाब देने के लिए तैयार है।

अमेरिका में ट्रक चालकों के लिए अंग्रेजी जरुरी, आदेश से सिख समुदाय चिंतित

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में ट्रक चालकों के लिए अंग्रेजी में अनिवार्यता को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया हैं। इस आदेश को लेकर सिख अधिकार समूहों ने चिंता जाहिर की है। इन समूहों ने कहा है कि आदेश का सिख समुदाय के ट्रक चालकों पर ''भेदभावपूर्ण प्रभाव'' पड़ सकता है और रोजगार में अनावश्यक बाधाएं पैदा हो सकती हैं। आदेश में कहा गया है, अंग्रेजी में दक्षता पेशेवर चालकों के लिए सुरक्षा संबंधी अनिवार्यता होनी चाहिए। वे यातायात संकेतों को पढ़ने और समझने में सक्षम हो, उन्हें यातायात सुरक्षा, सीमा गश्त, कृषि चौकियों और माल वजन-सीमा स्टेशन के अधिकारियों के साथ संवाद करना आना चाहिए। ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है। 'सिख कोलिशन' संगठन कहा कि वे ट्रंप के आदेश से ''काफी चिंता'' में है।

हार्वर्ड विश्वविद्यालय में यहूदी विरोधी और इस्लामोफोबिया का साया, रिपोर्ट जारी की, किया बदलाव का वादा

वाशिंगटन

संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान हार्वर्ड विश्वविद्यालय पिछले कुछ समय से यहूदी विरोधी और इस्लामोफोबिया की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की मंगलवार को सार्वजनिक की गई रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। हार्वर्ड ने इसमें बदलाव का वादा किया है। उल्लेखनीय है कि हार्वर्ड ने पिछले दिनों फंड में कटौती का विरोध करते हुए ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

खबर के अनुसार, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने यहूदी विरोधी और इस्लामोफोबिया पर रिपोर्ट के बाद बदलाव का वादा किया है। यह दोनों रिपोर्ट हार्वर्ड टास्क फोर्स ने जारी की हैं। हार्वर्ड टास्क फोर्स ने कहा है कि यहूदी विरोधी भावना ने पाठ्यक्रम, सामाजिक जीवन, कुछ संकाय सदस्यों की नियुक्ति और कुछ शैक्षणिक कार्यक्रमों के वैश्विक दृष्टिकोण में घुसपैठ कर ली है।

हार्वर्ड टास्क फोर्स ने कैंपस में अरब विरोधी, मुस्लिम विरोधी और फिलिस्तीन विरोधी पूर्वाग्रह पर एक अलग रिपोर्ट भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अधिकांश मुस्लिम विद्यार्थियों को अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने के लिए शैक्षणिक या पेशेवर दंड का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन कैंपस में यहूदी विरोधी भावना के आरोपों की जांच कर रहा है। विश्वविद्यालय संघीय निधि में अरबों डॉलर वापस लेने का विरोध कर रहा है।

द बोस्टन ग्लोब की खबर के अनुसार, इस रिपोर्ट के आने के बाद अरब और मुस्लिम विद्यार्थियों ने कहा कि कैंपस में उन्हें दोयम दर्जे के नागरिक जैसा महसूस होता है। साथी उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन के साथ अपने असाधारण टकराव के बीच दोनों रिपोर्ट मंगलवार को जारी की हैं। दोनों रिपोर्ट पिछले साल शरद ऋतु में जारी की जानी थी। ट्रंप प्रशासन ने 19 अप्रैल को मांग की थी कि हार्वर्ड यहूदी विरोधी रिपोर्ट से संबंधित सभी दस्तावेज सौंपे।

उल्लेखनीय है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय मैसाचुसेट्स राज्य के कैम्ब्रिज शहर में स्थित है। यह एक निजी शोध विश्वविद्यालय है और आईवी लीग का सदस्य है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान है।

एस-400 मिसाइल पड़ोसी को मिली, लेकिन भारत की ज्यादा पावरफुल

मॉस्को। रूस की एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली को दुनिया की सबसे एडवांस वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। भारत के बाद अब चीन भी इस प्रणाली को हासिल कर चुकी है। लेकिन रूस ने चीन को जो एस-400 मिसाइलें सप्लाई की हैं उसमें वो आधुनिक तकनीक को शामिल नहीं किया गया है जो भारत की मिसाइलों में है एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने चीन को दी गई इन प्रणालियों में जानबूझकर कुछ एडवांस सुविधाओं को सीमित या अक्षम कर दिया है, जिससे बीजिंग कथित तौर पर हैरान और निराश है। 2014 में, चीन ने रूस के साथ कई अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत उसे एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल की कई यूनिट प्राप्त होनी थीं। यह सौदा रूस-चीन सैन्य सहयोग का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना गया था और इसे चीन की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। हालांकि, चीनी विश्लेषकों ने हाल ही में देखा कि ये मिसाइलें चीनी सेना के सार्वजनिक प्रदर्शनों या रिपोर्टों में शायद ही नजर आती हैं। चीनी मीडिया के अनुसार, रूस ने चीन को एस-400 का एक सामान्य वर्जन प्रदान किया है, जिसमें कई एडवांस तकनीकी सुविधाएं जानबूझकर बंद कर दी गई हैं। यह कदम रूस द्वारा अपनी तकनीकी गोपनीयता की रक्षा करने और विदेशी सेनाओं को अपनी सैन्य क्षमताओं से प्रतिस्पर्धा करने से रोकने के लिए उठाया गया माना जा रहा है। रूसी रक्षा सूत्रों की मानें, तो सभी एक्सपोर्ट की जाने वाली हथियार प्रणालियों को ई इंडेक्स के साथ चिह्नित किया जाता है और इनमें सीमित क्षमताएं होती हैं। उन देशों के लिए जो रूस के संभावित प्रतिद्वंदी नहीं हैं, उनको दिए जाने वाले हथियारों की क्षमताएं भिन्न हो सकती हैं।

यूएनएससी में पाकिस्तान को घेर रहे थे जयशंकर, तभी रुस ने कर दी हां में हां

जिनेवा

पाकिस्तान हर एक मोर्चे पर मुंह की खा रहा है। इसके बाद भी उसे अक्ल नहीं आ रहीं है। यूएनएससी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को घेरा ही था कि रुस ने भारत का समर्थन करते हुए हां में हां कर दी। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक घेराबंदी तेज कर दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सभी अस्थायी सदस्यों से संपर्क साधा और आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश देने का आग्रह किया। इसकी जिम्मेदारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद संभाली है। उन्होंने अल्जीरिया, ग्रीस, गुयाना, पनामा, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया जैसे देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है। ये सभी फिलहाल यूएनएससी के अस्थायी सदस्य हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी फोन पर चर्चा की है। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि गुटेरेस ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है और हमलावरों को सजा दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन किया है।

हालांकि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान चाह रहा था कि जम्मू-कश्मीर को विवादित क्षेत्र कहा जाए, लेकिन भारत ने उसे अमेरिका और फ्रांस की मदद से रोक दिया। सुरक्षा परिषद ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हमलावरों, योजनाकारों, फंड देने वालों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकी संगठनों को समर्थन दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योगना पटेल ने इस बयान को पाकिस्तान की असली सोच का पर्दाफाश बताया और कहा कि पाकिस्तान एक दुष्ट राष्ट्र बन चुका है जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।

फैटी लिवर से काफी बढ़ जाता है डिजीज का खतरा

हेल्थ विशेषज्ञों के अनुसार, जंक फूड में खराब वसा, अधिक मात्रा में चीनी और प्रोसेस्ड पदार्थ शामिल होते हैं, जो शरीर में मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल और टाइप-2 डायबिटीज जैसी बीमारियों के खतरे को बढ़ाते हैं। लिवर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छी नींद लेना और जंक फूड से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। इन बीमारियों के चलते नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (एनएएफडी) का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। यह बीमारी समय के साथ सिरोसिस या लिवर कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों में बदल सकती है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि जंक फूड को रोजाना खाने की आदत लिवर के लिए बेहद हानिकारक है। उनके अनुसार, जंक फूड का नाम ही बताता है कि यह कचरे के समान है और इसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पेट और आंतों को कचरे का डिब्बा नहीं समझता, तो उसे ऐसे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। लिवर को स्वस्थ रखने के लिए केवल सही खानपान ही नहीं, बल्कि पर्याप्त और सही समय पर नींद लेना भी आवश्यक है। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो लोग ठीक से नींद नहीं लेते, उनमें फैटी लिवर डिजीज होने का खतरा कई गुना अधिक बढ़ जाता है। देर रात जागने और देर से भोजन करने की आदतें पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी प्रभावित करती हैं, जो शरीर की संपूर्ण सेहत के लिए आवश्यक हैं। रात को देर से खाना खाने से वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे ये तत्व लिवर में जमा हो जाते हैं और लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं।

बांग्लादेश के आगामी बजट में सामाजिक सुरक्षा पर जोर, प्रस्तावों को मंजूरी

ढाका

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आगामी राष्ट्रीय बजट (2025-26) में सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है। वित्त सलाहकार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद ने बजट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस बजट में 624,000 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। सभी प्रकार के लाभों के लिए भत्ते में न्यूनतम 50 टका से अधिकतम 100 टका की वृद्धि की जाएगी।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। इसमें कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर सलाहकार परिषद समिति की हाल ही में हुई बैठक में वित्त सलाहकार अहमद ने प्रस्तावों को मंजूरी दी। आगामी बजट में 12 प्रकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कुल आवंटन 19,707 करोड़ टका होगा। चालू वित्त वर्ष (2024-25) में आवंटन 17,957 करोड़ टका था।

वित्त विभाग के अनुमान के अनुसार, 2025-26 में 99,000 नए लाभार्थियों को जोड़कर कुल 6.1 मिलियन बुजुर्गों को वृद्धावस्था भत्ता मिलेगा। इस भत्ते की राशि में 50 टका की वृद्धि की गई है, जो 600 टका से बढ़कर 650 टका हो गई है। इस कार्यक्रम के लिए कुल 4,791.31 करोड़ टका आवंटित किए जाएंगे, जो मौजूदा बजट में 4,350.97 करोड़ टका से अधिक है। इसके अलावा विधवा भत्ता श्रेणी में अतिरिक्त 125,000 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। बजट प्रस्तावों में 800,000 गैरकैडर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के लिए 27,413.78 करोड़ टका आवंटित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, 219,000 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भत्ते के रूप में 5,176.71 करोड़ टका आवंटित किया गया। विकलांगता भत्ता कार्यक्रम के लिए लाभार्थियों की संख्या 3.234 मिलियन से बढ़ाकर 3.45 मिलियन की गई है। इसके भत्ते को 50 टका बढ़ाकर 900 टका किया जाएगा। बांग्लादेश में मातृ एवं शिशु लाभ कार्यक्रम के तहत गरीब माताओं को वजीफा दिया जाता है। आगामी वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम में 115,920 नई लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। साथ मासिक भत्ता 50 टका से बढ़ाकर 850 टका कर दिया जाएगा।

मुजीब को नोटों से हटाने की जिद के चलते बांग्लादेश में करेंसी की हुई भारी किल्लत

ढाका

भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश कई चुनौतियों से जूझ रहा है। रही सही कसर बेतुके निर्णय के कारण पूरी हो रही है। जिसमें बांग्लादेश की करेंसी टका से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाने के फैसले से देश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस की सरकार में नोटों को लेकर लिया गया फैसला बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हालत यह है कि बांग्लादेश में करीब 15000 करोड़ टका की करेंसी प्रचलन से बाहर है। इन नोटों में बांग्लादेश के संस्थापक रहे शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें छपी थीं और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इन्हें प्रचलन से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार के डर से बैंक अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन

नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि इससे संकट पैदा हुआ है। नोटों की कमी से मार्केट में कारोबार ही ठप है। इसके अलावा बैंकों में भी लोग यदि पैसे निकालने जा रहे हैं तो करेंसी ही नहीं है कि कैश दिया जा सके। बैंकों ने केंद्रीय बैंक से नोटों की डिमांड की है, लेकिन अब तक सप्लाई नहीं हुई है। इस साल अप्रैल की शुरुआत में सरकार ने अचानक ही फैसला ले लिया कि उन सभी नोटों और सिक्कों को प्रचलन से बाहर किया जाएगा, जिनमें शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हैं। यह फैसला लेने से पहले कोई नई करेंसी छापी नहीं गई थी। ऐसे में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। भारत में 2016 में नोटबंदी हुई थी और उससे पहले बड़े पैमाने पर 500 और 2000 रुपये के नोट छापे गए थे। ऐसे में अचानक नोटबंदी के फैसले का उतना असर नहीं दिखा था। बांग्लादेश की स्थिति यह है कि मुजीबुर रहमान की तस्वीरों वाले नोटों से कारोबार बंद है और नए नोट अभी बाजार में आए नहीं हैं। बांग्लादेश बैंक का कहना है कि नए नोटों की छपाई मई में शुरू होगी। ऐसे में यह सवाल है कि कब नोट छपेंगे और कब बैंकों एवं बाजारों में आएंगे। सूत्रों का कहना है कि पहले राउंड में 20, 50 और 1000 टका के नोट छापे जाएंगे।

पाकिस्तान ने कहा अमेरिका के लिए गंदा काम किया, यूएस से सच पूछा तो बगले झांकने लगा

वॉशिंगटन। अमेरिका अपनी बात से मुकरता है और झूठ भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसका ताजा उदाहरण पाकिस्तान का वो बयान है जिसमें उसने कहा था की अमेरिका के कहने पर 30 साल आतंकियों को पोषित किया है। इस मामले में जब अमेरिका से पूछा गया तो वो बगलें झांकने लगा और घुमा फिराकर जवाब दिया। जब वाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में इस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, हम भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के संपर्क में हैं। हम क्षेत्र में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस तनावपूर्ण माहौल के बीच दोनों देशों को बातचीत से समाधान निकालने की सलाह दी है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत और पाकिस्तान के अपने समकक्षों से शीघ्र बातचीत करेंगे। टैमी ब्रूस ने कहा, हम सभी पक्षों से आग्रह कर रहे हैं कि वे जिम्मेदार रवैया अपनाएं। पूरी दुनिया इस स्थिति को देख रही है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका सिर्फ मंत्री-स्तर पर नहीं, बल्कि कई स्तरों पर भारत और पाकिस्तान के साथ संपर्क में है। बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया सनसनीखेज कबूलनामे के बाद हड़कंप मच गया है।